

आयोजन

हमारी सरकार ने जनजातीय महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया : डॉ यादव

आजादी के बाद सरकारों ने की वोट बैंक की राजनीति : सीएम

अमर शहीदों को नमन
कर अर्पित की श्रद्धांजलि

जबलपुर। हमारी सरकार ने जनजातीय महापुरुषों राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जैसी विभूतियों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। प्रदेश की भावी पीढ़ियाँ उनके बलिदान और जीवन के प्रेरणादायी कार्यों से परिचित होंगी। आजादी के बाद लंबे समय तक देश-प्रदेश में रही सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद को जनजातीय समुदाय की श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने सुशोभित किया। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय के जननेता विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। राज्य सरकार रानी दुर्गावती लोक का निर्माण करेगी, निमाड़ के जनजातीय नायक क्रांतिसूर्य टंट्या मामा के नाम पर



खरगोन में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बुंदेलखंड के सागर में भी रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। जनजातीय समुदाय के गौरवशाली अतीत को सबके सामने लाना राज्य सरकार का दायित्व है। सरकार जनजातीय महापुरुषों और बलिदानियों के जीवन पर फिल्म तैयार करने सहित सभी योजना को प्रोत्साहित कर रही है। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में जनजातीय महानायक राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

आगे उन्होंने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से पहले अपनी कलम और कविताओं के बल पर मध्यप्रदेश के जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अलख जगाई थी। अंग्रेजों के दमन के विरोध में उस समय में जो काम तलवार नहीं कर पाई, वह राजा शंकर शाह की लेखनी ने कर दिखाया। उनके लिखे गीतों ने जनता के बीच आजादी की ललक और अलख जगा कर नई ऊर्जा का संचार किया। वे देश और धर्म को साथ लेकर चले। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह का

बलिदान अद्भुत और सदैव स्मरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 169वें बलिदान दिवस पर माल गोदाम चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिमा स्थल के समीप बन देव स्थल पर पूजन-अर्चन भी किया।

गौरवशाली विरासत का अहम अध्याय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजा शंकर शाह ने कविताओं और गीतों के माध्यम से जनजागरण का कार्य किया। पिता-पुत्र का बलिदान देश की गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने और उनके इतिहास का संकलन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

52 गढ़ों के वंशजों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह सहित प्रदेश के अनेक महापुरुषों की जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों को पाठ्यक्रम में शामिल कर सम्मान दिया है। हमारे जनजातीय वीरों ने अंग्रेजों से क्षमा-याचना नहीं की। आज हम सभी पवित्र भूमि जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहादत का स्मरण कर रहे हैं। जनजातीय कार्यमंत्री कुंदर विजय शाह ने कहा कि जनजातीय वीरों और महापुरुषों को देश की भावी पीढ़ी याद रखे, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी जनजातीय छात्रवासों के नाम जनजातीय महानायकों के नाम पर रखे हैं। अब हमारी सरकारने पाठ्यपुस्तकों में जनजातीय महापुरुषों के योगदान को शामिल किया है। भावी-पीढ़ी इससे परिचित होगी। मंत्री श्री शाह ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर को वीरगंगा रानी दुर्गावती की जयंती है, इस अवसर पहली बार उनके 52 गढ़ों के वंशजों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। जबलपुर के अलावा हरसूद में भी रानी दुर्गावती की जयंती पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

डूब क्षेत्र में ही बनाने लगे नया स्कूल भवन

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने उस मामले को सख्ती से लिया है, जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाले स्कूल को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित लेने का निर्णय लेते हुए महज बीस फिट की दूरी पर नया भवन निर्माण शुरू कर दिया गया। दायर मामले में आरोप है कि शासकीय राशि का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, यह उसकी वानगी है। चीफ जस्टिस अल्फ्रेड यशवंत कोण्डे व जस्टिस विवेक रूसिया की युगलपीठ ने मामले में किये गये दावे को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब तलाब किया है। यह जनहित का मामला चन्द्रबद

ग्राम के निवासी जगदीश गुर्जर, गुलाब सिंह एवं नंदराम अहिरवार की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि सीहोर जिले में चन्द्रबद ग्राम पंचायत को पार्वती बांध परियोजना के तहत डूब प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। जिससे खसरा नंबर-33/1 के आठ कुल रकबा 4, 293 हेक्टेयर में से 4, 213 की जमीन डूब क्षेत्र में आ गई। उक्त भूमि पर ही शासकीय स्कूल का भवन बना हुआ था। जिसने अन्यत्र स्थान पर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए दूसरी

जगह नया भवन बनाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन उक्त नया भवन, वर्तमान भवन से महज बीस फिट की दूरी पर ही बनाया जाने लगा। जिस पर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति पेश की, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। मामले में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने तर्क दिया कि डूब प्रभावित एरिया में स्कूल भवन बनाने से बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न निहित है क्योंकि पानी के आस-पास स्कूल भवन बनाने से बच्चे स्वाभाविक रूप से खेलेंगे।

8 माह में ही जर्जर हुई सड़क, वार्डवासियों के साथ कांग्रेस पार्षद दल ने किया प्रदर्शन

नवभारत, जबलपुर। नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर की खस्ताहाल सड़कों एवं नगर निगम की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान एवं पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड के वार्डवासियों के साथ शुक्रवार को यातायात थाने के सामने महाराष्ट्र हाई स्कूल रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्षद दल ने मांग की कि महाराष्ट्र हाई स्कूल रोड के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, सड़क को निरधारित मापदंडों के अनुसार दोबारा दुरुस्त कराया जाए तथा यदि निर्माण में



अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

पहली बरसात में उखड़ी सड़क

इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने

करोड़पति निकला रादुविवि क्लर्क, मिली आय से अधिक संपत्ति

सेवाकाल की कमाई 91 लाख खर्च कर डाले 1.68 करोड़
लोकायुक्त ने 85 प्रतिशत अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया



जबलपुर। लोकायुक्त ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ उच्च वर्ग लिपिक बंश बहोर पटेल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में क्लर्क करोड़पति निकला है। क्लर्क ने अपनी वैध कमाई से 85.57 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की और खर्च किया है। सेवाकाल की कमाई 91 लाख है और उसने 1.68 करोड़ खर्च कर डाले हैं। लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में उच्च वर्ग लिपिक 62 वर्षीय बंश बहोर पटेल पिता कालूराम पटेल के खिलाफ 2024 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिली थीं। जिसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। लंबी जांच जांच पड़ताल में लिपिक की वैध स्रोतों से कुल 91,88,611 रुपये की आय पाई गई। कुल व्यय 1,68,51,337 रुपये पाया गया। वैध आय से 85.57 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई

गई। अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से इतनी बड़ी मात्रा में अधिक खर्च और निवेश करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद लोकायुक्त जबलपुर ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

41 साल की नौकरी में जुटाई काली कमाई

बंश बहोर पटेल ने अपनी 41 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति जुटाई है। बंश बहोर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वर्ष 1985 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में पदस्थ हुआ। थोर-थोर उसने विविध में पैर जमाए और वर्ष 1994 में खुद की

नियुक्ति बतौर नियमित कर्मचारी करा ली थी। इसके बाद उसने 41 सालों में काली कमाई जुटाई।

तीन आलीशान घर गाड़ियां मिलीं

लोकायुक्त निरीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि उसके तीन आलीशान घर में मिले। महुगंज, हिनौतिया, सालीवाड़ा, नीमखेड़ा में उसकी संपत्तियां मिली हैं। वहीं उसके घर में फोरव्हीलर और टूव्हीलर वाहन भी मिले हैं। चार से छह दुपहिया और चार पहिया वाहनों का रेलवा भी हिनौतिया में कृषि भूमि भी उसने खरीदी है। मामले की जांच पड़ताल जारी है।

शहीद राजाओं को गार्ड ऑफ ऑनर देने की उठी आवाज

शहादत स्थली की उपेक्षा पर फूटा आक्रोश
कीर्ति स्तंभ निर्माण और विकास की उठी मांग

नवभारत, जबलपुर। अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की शहादत स्थली की उपेक्षा को लेकर विभिन्न जन संगठनों ने शुक्रवार को शहादत स्थली पर आधे घंटे धरना-प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अमर शहीद राजाओं की गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने और शहादत स्थली के समुचित विकास की



मांग प्रमुखता से उठाई। धरने में गोंडवाना महासभा, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर, गोंडवाना जन जागृति संघ एवं गोंडवाना जन जागृति एवं विकास समिति के

पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठनों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से शहादत स्थली पर भव्य कीर्ति स्तंभ बनाए जाने की मांग की जा रही है, जिसमें आदिवासी साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास

का उल्लेख हो। साथ ही अमर शहीद आदिवासी राजाओं की गार्ड

ऑफ ऑनर देने की मांग भी की जाती रही है।

ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे को लेकर जताई आपत्ति

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहादत स्थली पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव तथा स्थल के पीछे लगाए गए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने खंभे को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने, शहादत स्थली का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण करने और इसे गरिमापूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित करने की मांग प्रशासन से की। धरना-प्रदर्शन में पूर्व मंत्री व पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री कौशल्या गोठिया, रामरतन यादव, घनश्याम यादव, सौरभ शर्मा, कमल कोरचे, संजू ठाकुर, मुकेश बड़ी, संजय इक्का, भान सिंह, सुधीर शर्मा, देवेंद्र यादव, प्रमोद सेन, सोनू वरकड़े, शिवाजी धुर्वे, कुंजी गोठिया, क्रांति मरावी, दिवाकर चौधरी सहित बड़ी संख्या में आदिवासी, मूल निवासी एवं संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर के साथी उपस्थित रहे।

नई ई-बस भेड़ाघाट में हुई खराब, यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी

शुरुआत के साथ ही संचालन और मेटेनस व्यवस्था पर उठे सवाल

जबलपुर। शहर में शुरू की गई नई ई-बस सेवा को लेकर यात्रियों में सुविधा की उम्मीद जगी थी, लेकिन सेवा शुरू होने के साथ ही बस के बीच रास्ते खराब होने की घटना सामने आ गई। भेड़ाघाट क्षेत्र में चल रही एक नई ई-बस तकनीकी खराबी के कारण



अचानक खड़ी हो गई। बस रुकने से उसमें सवार यात्रियों को कुछ देर परेशानी का सामना करना पड़ा और सफर प्रभावित हुआ। नई बस के इस तरह बीच रास्ते खड़े होने से ई-बस सेवा की तैयारियों पर

सवाल खड़े हो गए हैं। खासतौर पर जब नई बसों को शहर के प्रमुख मार्गों और पर्यटन क्षेत्र भेड़ाघाट तक यात्रियों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उतारा गया है। यात्रियों का कहना है कि नई बसों से सुगम और निर्बाध सफर की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत में ही तकनीकी खराबी सामने आने से व्यवस्था की वास्तविक तैयारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मेटेनस पर भी नजर जरूरी

ई-बसों के नियमित संचालन के साथ उनकी तकनीकी जांच और समय पर मेटेनस बेहद जरूरी है। शहर में ई-बस सेवा का विस्तार होने जा रहा है, ऐसे में शुरुआती दौर में सामने आई इस खराबी को महज एक घटना मानकर छोड़ने के बजाय इसकी वजह और तकनीकी स्थिति की जांच जरूरी है। यात्रियों की सुविधा तभी कायम रहेगी।



पत्नी की इच्छा के सम्मान में जस्टिस सिंह ने लिया संकल्प, करेंगे देहदान

पीएम राहत को में देंगे जीपीएफ की 1 करोड़ 1 लाख की राशि

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनीन्द्र कुमार सिंह गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर-1 में दोपहर 3.30 बजे फुल कोर्ट फेयरेवेल आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान जस्टिस सिंह और उनकी पत्नी इंदिरा सिंह ने एक ऐसा संकल्प लिया, जिसने समारोह में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा।

जस्टिस श्री सिंह ने घोषणा की कि वे और उनकी पत्नी देहदान करेंगे। इसके लिए दो दिन पहले उन्होंने मोंडिकल कॉलेज में आवेदन भी कर दिया है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के

बाद मिलने वाली जीपीएफ की करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही जीपीएफ की राशि उनके खाते में आएगी, वह तत्काल उसे राहत कोष में ट्रांसफर कर देंगे।

समाज के लिए लिया संकल्प

अपने विदाई समारोह में जस्टिस सिंह कई बार भावुक हुए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी इंदिरा की इच्छा थी कि वे समाज के लिए कुछ करें। पत्नी की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने देहदान और जीपीएफ की राशि समाजहित में देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि जीपीएफ की राशि खाते में आते ही उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

जस्टिस अनीन्द्र कुमार सिंह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के पहले जज हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर इस तरह का सार्वजनिक संकल्प व्यक्त किया है।

मौसी ने बेटे की तरह पाला

जस्टिस सिंह ने अपने जीवन के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि जब वे केवल 6 माह के थे, तब उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनके पिता के साथ उनकी मौसी स्वर्गीय निर्मला बुच, जो मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव थीं। और मौसा स्वर्गीय महेश नीलकंठ बुच ने उन्हें बेटे की तरह पाला। अपने संबोधन में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े इन प्रसंगों को साझा किया तो समारोह का माहौल भावुक हो गया।

पहल

नवभारत की पहल के बाद पमरे ने रेलवे बोर्ड और दफ्तरे को भेजा प्रस्ताव

चित्रकूट एक्सप्रेस को नैनपुर तक बढ़ाने की कवायद

अभी बस में लगते हैं 2200 रुपये, ट्रेन में लगेंगे सिर्फ 395

धनंजय श्रीवास्तव
जबलपुर, नवभारत। मंडला-नैनपुर अंचल के यात्रियों के लिए लखनऊ तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की उम्मीद अब पहले से मजबूत हुई है। नवभारत द्वारा पहले भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा चुका है, जिसके बाद अब लखनऊ-जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस को नैनपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रेलवे स्तर पर आगे भेजा गया है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यात्रियों के लिए किराए में भी बड़ा अंतर सामने आएगा। अभी जबलपुर से बस के जरिए लखनऊ

पहुंचने और फिर मंडला जाने में करीब 2200 खर्च होते हैं, जबकि ट्रेन से लखनऊ-जबलपुर का किराया करीब 355 और जबलपुर-नैनपुर का किराया 35 से 40 है। यानी करीब 395 में नैनपुर तक रेल सफर का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।



नवाबों की नगरी से जुड़ेगा आदिवासी अंचल

यह पहल अगर कागज से

लगातार उठती रही है मांग

इस प्रस्ताव के पीछे रेलवे के पास रैक के बेहतर उपयोग का तर्क भी है। 15205 चित्रकूट एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर सुबह 5.40 बजे जबलपुर पहुंचती है, जबकि वापसी में 15206 रात 8.50 बजे जबलपुर से लखनऊ के लिए रवाना होती है। इस बीच करीब 14 घंटे तक रैक जबलपुर गार्ड में खड़ा रहता है। इसी खाली समय का उपयोग करते हुए ट्रेन को नैनपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे को भेजा गया है। बता दें कि मंडला फोर्ट स्टेशन तैयार होने के बाद यहां से लखनऊ सहित बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन की मांग लगातार उठती रही है। नैनपुर तक ट्रेन बढ़ती है तो मंडला क्षेत्र के यात्रियों को जबलपुर आकर ट्रेन पकड़ने की परेशानी कम होगी और जबलपुर गार्ड में खड़े रैक का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। अभी बस से जबलपुर से लखनऊ की दूरी 420 किलोमीटर है और समय करीब 18-23 घंटे का लग रहा है। वहीं जबलपुर से मंडला की दूरी 90 किमी है जिसे बसे पूरा करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय ले रही है। बात करें अगर ट्रेन से यात्रा की तो, यही सफर नैनपुर से लखनऊ का करीब 15 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा।

निकलकर सच साबित हुई और ट्रेन नैनपुर तक पहुंची, तो इसका सीधा फायदा मंडला-नैनपुर के यात्रियों को मिलेगा। आदिवासी अंचल का यह क्षेत्र नवाबों की नगरी लखनऊ से सीधे रेल नेटवर्क में जुड़ सकेगा, जिससे रोजगार, शिक्षा, व्यापार और आवागमन के लिए नई सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर जबलपुर पर यात्रियों का दबाव भी घटने की

संभावना है। इसी कड़ी में गढ़ा और ग्वारीघाट रेलवे स्टेशनों को दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के नागपुर मंडल से पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में शामिल करने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। अब दोनों प्रस्तावों पर रेलवे को मंजूरी का इंतजार है। फैसला हुआ तो जबलपुर और आसपास के रेल नक्शे में इसका असर साफ दिखाई देगा।

इनका कहना है

पश्चिम मध्य रेल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जानकारी हासिल कर आप को सूचित करता हूँ। आप के द्वारा चलाई जा रही यह पहल सराहनीय है। इसका पूरा लाभ यात्रियों को मिलेगा।

श्रेष्ठ रमराम,
सीपीआरओ, दफ्तरे